

5



छात्र राजनीति से  
राष्ट्रीय राजनीति  
तक का सफर

6



विशेष लेख:  
ब्रिक्स सम्मेलन  
एक लेखा-जोखा

7



देवतात्मा हिमालय  
पर प्रदूषण का  
आक्रमण

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 20

प्रति सोमवार, 5 अक्टूबर 2026

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

कवर  
स्टोरी



-विजया पाठक  
एडिटर

सागर के बंदा और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था, आवकरी तंत्र और राजनीतिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना केवल अवैध शराब बेचने वालों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने तक सीमित नहीं रह सकती। असली सवाल यह है कि जिस अवैध शराब के नेटवर्क ने इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को जन्म दिया, वह इतने समय तक सक्रिय कैसे रहा और उसके पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कारोबारी संरक्षण का कोई तंत्र था

## आखिर 38 मौतों के सौदागर का संरक्षक कौन है?

सागर में पिछले 5 सालों में जितनी  
आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं,  
उनका कहीं न कहीं कनेक्शन मंत्री  
गोविंद सिंह राजपूत से है



या नहीं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बंदा क्षेत्र में जहरीली शराब की घटना सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने एक संगठित नेटवर्क की बात सामने रखी है। पुलिस के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर शराब तैयार करने, उसे सस्ते दामों पर बेचने और गांवों तक पहुंचाने की कड़ियां सामने आईं।

**38 मौतों के दावे से उठे सवाल**

घटना के शुरुआती दिनों में मौतों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आते रहे। स्थानीय और राजनीतिक दावों में मृतकों की संख्या इससे अधिक बताई गई, जबकि प्रशासन और बाद में राज्य सरकार की न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में झूठ बोलते हुए 20 मौतों की बात कही। ऐसे में बड़े सवाल यह है कि आखिर इन 38 मौतों का सौदागर कौन है।  
(शेष पेज 2 पर)

लोहा चोर  
इंद्रजीत सिंह  
उर्फ छोटू अब  
सीबीआई के  
शिकंजे में

**बड़ा सवाल:** क्या  
अब जेल की सलाखों में  
जायेगा छोटू? बीजेपी-  
कांग्रेस के नेताओं और  
पुलिस अफसर भी आयेगे  
जांच के दायरे में



-विजया पाठक

ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति का एक ही मकसद है- सत्ता का सुख भोगना। सिंधिया को जनसेवा या जनकल्याण से कोई वास्ता नहीं है। यही कारण है कि वह केवल सत्तासीन पार्टी से जुड़कर रहना चाहते हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान भी सिंधिया ने यही किया था। अपने पिछलगू गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी और प्रदुप्य सिंह तोमर जैसे नेताओं के बल पर अपनी राजनीति संकेत करते हैं। सिंधिया की राजनीति में एक दौर ऐसा रहा है जब ग्वालियर-चंबल की सियासत में उनका नाम ही काफी माना जाता था। राजधराने की विरासत, कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में पहचान और ग्वालियर-चंबल में मजबूत व्यक्तिगत नेटवर्क- इन सबने मिलकर सिंधिया को मध्यप्रदेश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि किसी नेता का अतीत कितना मजबूत रहा है। सवाल यह होता है कि आज जमीन पर उसकी पकड़ कैसी है? यही सवाल इन दिनों सिंधिया के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में उनके कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाए गए। (शेष पेज 3 पर)

22 विधायकों के साथ  
कमलनाथ सरकार गिराई,  
सत्ता मिली लेकिन क्या  
सिंधिया ने खो दी अपनी  
पुरानी सियासी पकड़?

गौ-संरक्षण से पशुधन संवर्धन तक,  
छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाओं पर जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का गौधाम योजना पर फोकस

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण, निराश्रित पशुओं के प्रबंधन और पशुपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गौधाम योजना, गौशालाओं को वित्तीय सहायता, चारा विकास और पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने जैसे विषयों पर जोर दिया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के साथ गौपालकों, किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए पशुपालन को आजीविका का बेहतर माध्यम बनाना है। राज्य सरकार ने निराश्रित और घुमंतू गौवंश के संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू की। इसका औपचारिक शुभारंभ 14 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बिलासपुर से किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 29 गौधामों का उद्घाटन किया गया। योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के पूरा होने पर प्रदेश में कुल 1,460 गौधाम स्थापित करने की परिकल्पना है। गौधामों में पशुओं के लिए शेंड, बाड़बंदी, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। (शेष पेज 2 पर)



-विजया पाठक

भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से जुड़े बहुचर्चित लोहा चोरी और संगठित धोखाधड़ी के मामले में एक बहुत बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। इस बहुचर्चित प्रकरण की अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस बहुचर्चित मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए अपनी औपचारिक सहमति प्रदान कर दी है और इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके साथ ही इस गोरखधंधे में शामिल बीजेपी-कांग्रेस के नेता भी जांच के दायरे में आयेगे। उन पर भी अब सीबीआई का शिकंजा कसने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे मामलों में सीबीआई की भूमिका केवल अपराधियों की पहचान तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे तंत्र में मौजूद कमियों और संभावित मिलीभगत की भी जांच की जाती है। यह मामला केवल चोरी की जांच का विषय नहीं है, यह जवाबदेही की परीक्षा है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसका निर्धारण होना चाहिए। यदि किसी स्तर पर मिलीभगत हुई है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। (शेष पेज 3 पर)

# आखिर 38 मौतों के सौदागर का संरक्षक कौन है?

(पेज 1 का शेष)

क्यों प्रशासन इस सौदागर के संरक्षक को गिरफ्तार करने में असफल है। सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेता गोविंद सिंह राजपूत के तार इस पूरे मामले से बहुत करीब जुड़े हुए हैं। चर्चा है कि राजपूत के इशारे और संरक्षण में ही पूरे सागर जिले में जहरीली शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। यही नहीं राजपूत के संरक्षण में पिछले 05 सालों में जिले कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो गई है और भ्रष्टाचार, आपराधिक घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं।

## मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर उठे आरोपों की जांच क्यों जरूरी?

घटना के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर शराब कारोबार से जुड़े लोगों को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में उनके जन्मदिन पर शराब ठेकेदारों द्वारा विज्ञापन दिए जाने और कुछ लोगों के साथ उनके सार्वजनिक संपर्कों का उल्लेख भी किया गया। हालांकि ये राजनीतिक आरोप हैं और राजपूत ने इन्हें खारिज करते हुए कहा है कि उनका या उनके परिवार का अवैध अथवा जहरीली शराब के कारोबार से कोई संबंध नहीं है। यहीं से सवाल और गंभीर हो जाता है। यदि आरोप निराधार हैं तो जांच के माध्यम से उनकी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। और यदि जांच में किसी प्रकार का प्रशासनिक, कारोबारी या राजनीतिक संबंध सामने



(विजयभ)

आता है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। बड़ा सवाल यह भी है कि मंत्री की जानकारी के बगैर क्यों से उनके क्षेत्र में कैसे इतना बड़ा अवैध शराब का कारोबार चल सकता है। निश्चित ही कहीं न कहीं इसके तार मंत्री राजपूत से जुड़े हुए हैं।

## पार्टी और संगठन ने साध रखी है चुप्पी

आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अभी तक पार्टी और संगठन ने इस पूरे मामले पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से किसी प्रकार से बातचीत करना तक उचित नहीं समझा। यही कारण है कि मंत्री राजपूत

लगातार इस पूरे कारोबार को निचले स्तर तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। अगर समय रहते पार्टी ने इस पर शिकंजा कस दिया होता तो यह नौबत नहीं आती और आम जनता को जनहानि नहीं होती। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन मौतों के लिए सरकार किसे जिम्मेदार ठहराएगी। इतनी बड़ी घटना के बाद केवल पुलिस और आबकारी अधिकारियों से जवाब मांगना पर्याप्त नहीं होगा। गोविंद सिंह राजपूत क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में उन पर लगे आरोपों की

स्वतंत्र जांच होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि किसी राजनीतिक व्यक्ति की छवि केवल आरोपों के आधार पर खराब न हो और यदि कोई वास्तविक प्रशासनिक या राजनीतिक कड़ी हो तो वह भी जांच से सामने आए। पार्टी और संगठन को भी यही पारदर्शिता दिखानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या संगठन ने मंत्री से इन आरोपों पर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा? क्या यह पता लगाने का प्रयास हुआ कि शराब कारोबारियों और स्थानीय राजनीतिक तंत्र के बीच कोई संपर्क था या नहीं? क्या संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की गई?

## बंडा में वर्षों से चल रहे नेटवर्क की जांच

स्थानीय लोगों के अनुसार सागर की इस घटना ने बंडा क्षेत्र में अवैध शराब के पुराने नेटवर्क की चर्चा भी तेज कर दी है। पुलिस जांच में सामने आए विवरणों के अनुसार कथित नेटवर्क में शराब तैयार करने, अलग-अलग स्थानों पर पहुंचाने और गांवों में स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से बेचने की कड़ियां थीं। कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को यह भरोसा दिलाया गया कि सस्ती शराब नकली नहीं है बल्कि वही ब्रांड है जिसे कथित तौर पर उसी "फॉर्मूले" से तैयार किया गया है। यह विवरण बताता है कि मामला किसी एक बोटल या किसी एक दुकान तक सीमित नहीं था। जांच में स्थानीय विक्रेताओं, कथित निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और लाइसेंसधारी शराब कारोबार से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को मुख्य आरोपी के रूप में चिह्नित करते हुए कई गिरफ्तारियां की हैं।

# गौ-संरक्षण से पशुधन संवर्धन तक, छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाओं पर जोर

(पेज 1 का शेष)

इसका संचालन पंजीकृत गौशाला समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, सहकारी समितियों और अन्य पात्र संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

## 36 गौधामों को प्रशासनिक स्वीकृति

पशुधन विकास विभाग की जानकारी के अनुसार, योजना के प्रारंभिक चरण में 36 गौधामों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, जबकि 29 का छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग में पंजीयन किया गया था। यह व्यवस्था आगे बढ़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित पशुओं के प्रबंधन और उनके नियमित भरण-पोषण में मदद कर सकती है। हालांकि, निर्धारित लक्ष्य और वास्तव में संचालित गौधामों की संख्या अलग-अलग है। इसलिए योजना की प्रगति का आकलन वास्तविक संचालन, पशुओं की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया जाना जरूरी है।

गौधामों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत गौधामों में रखे जाने वाले पशुओं के भरण-पोषण के लिए चरणबद्ध वित्तीय सहायता का प्रावधान बताया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पहले वर्ष प्रति गौवंश प्रतिदिन 10 रुपए, दूसरे वर्ष 20 रुपए, तीसरे वर्ष 30 रुपए और चौथे वर्ष से 35 रुपए प्रतिदिन सहायता देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अधोसंरचना निर्माण और मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक का प्रावधान बताया गया है। गौधामों में कार्य करने वाले चरवाहों के लिए 10,916 रुपए तथा गौसेवकों के लिए 13,126 रुपए मासिक मानदेय का भी उल्लेख किया गया है। चारा विकास के लिए प्रति एकड़ 47 हजार रुपए वार्षिक सहायता का प्रावधान अधिकतम पांच एकड़ तक लागू होने की जानकारी दी गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य गौधामों को केवल आश्रय स्थल के रूप में नहीं, बल्कि नियमित देखभाल वाली इकाइयों के रूप में संचालित करना है। सहायता की वास्तविक उपलब्धता संबंधित दिशा-निर्देशों, पात्रता और स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

## गौशालाओं को सहायता और चारे की व्यवस्था

गौवंश संरक्षण में पहले से संचालित गौशालाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौशालाओं के लिए सहायता बढ़ाने की जानकारी दी थी। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्रति गाय चारा अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने और पात्र

गौशालाओं को 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई। इसका उद्देश्य गौशालाओं में चारे, रखरखाव और पशुओं की देखभाल के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग गौशालाओं के पंजीयन, निरीक्षण, रखरखाव और अनुदान संबंधी कार्यों में भूमिका निभाता है। आयोग के पोर्टल पर गौशाला पंजीयन, अनुदान आवेदन, निरीक्षण तथा गौधाम से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आयोग का घोषित उद्देश्य देशी गौवंश के संरक्षण के साथ गौशालाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाना भी है। गौशालाओं को सहायता का लाभ तभी व्यापक रूप से मिल सकता है, जब चारे की नियमित उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त जगह, पशु चिकित्सक की पहुंच और अनुदान के उपयोग की निगरानी सुनिश्चित हो। इसके लिए वित्तीय सहायता के साथ जवाबदेही की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।

## पशुपालन को आजीविका से जोड़ने पर जोर

राज्य में पशुधन विकास की योजनाओं का दायरा केवल गावों तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन के नागरिक योजनाओं के पोर्टल पर उन्नत नस्ल के सांड वितरण, कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछियों के पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन और पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य पशुधन की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण परिवारों को आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है। उन्नत नस्ल के सांडों की उपलब्धता दूरस्थ क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। वहीं, कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछियों के पालन की योजनाएं दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं। बकरी और कुक्कुट पालन जैसी गतिविधियां छोटे तथा सीमांत किसानों और ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत बन सकती हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्रता, आवेदन, विभागीय स्वीकृति और उपलब्ध बजट के अनुसार मिलता है। इसलिए इच्छुक पशुपालकों के लिए संबंधित पशु चिकित्सा संस्थान या पशुधन विकास विभाग से वर्तमान दिशा-निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है।

## पशु चिकित्सा और रोग नियंत्रण भी महत्वपूर्ण

गौवंश तथा अन्य पशुधन का संरक्षण केवल आश्रय उपलब्ध कराने से पूरा नहीं होता। पशुओं का नियमित टीकाकरण, रोगों की समय पर पहचान, उपचार, प्रजनन संबंधी सेवाएं और पोषिक आहार भी जरूरी हैं। केंद्र

सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाएं छत्तीसगढ़ में भी लागू हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में पशुधन उत्पादकता, चारा उपलब्धता, स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और पशुपालकों की आजीविका बढ़ाने जैसे उद्देश्य शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने से बीमारी के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही पशुपालकों को पशुओं के पोषण, प्रजनन और वैज्ञानिक देखभाल के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है।

## गोबर का उपयोग और जैविक खेती की संभावनाएं

गाय के गोबर और गौशालाओं से निकलने वाले जैविक पदार्थों का उपयोग खाद, वर्मी कम्पोस्ट और बायोगैस जैसे उत्पादों के लिए किया जा सकता है। इससे पशुपालन और कृषि के बीच उपयोगी संबंध बन सकता है। यदि गौधामों में गोबर के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, जैविक खाद निर्माण और स्थानीय विपणन की व्यवस्था विकसित होती है, तो इससे अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण रोजगार को भी लाभ मिल सकता है। हालांकि, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू की गई गोधन न्याय योजना में गोबर की खरीद, गौठानों और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की व्यवस्था शामिल थी। इस योजना को वर्तमान सरकार की नई पहल बनाना सही नहीं होगा। वर्तमान में इसके संचालन, भुगतान और लाभार्थियों की स्थिति का आकलन करने के लिए अद्यतन आधिकारिक आंकड़ों की आवश्यकता है।

## योजनाओं का वास्तविक लाभ और आगे की चुनौतियाँ

गौ-संरक्षण और पशुधन विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय, गौशालाओं को आर्थिक सहायता, पशु चिकित्सा सेवाएं और नस्ल सुधार की पहल किसानों तथा ग्रामीण समुदायों की जरूरतों से जुड़ी हैं। गौधामों के प्रभावी संचालन से सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और फसलों को नुकसान जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायता मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि गौधामों में पशुओं की संख्या, उनके स्वास्थ्य, चारे की उपलब्धता, अनुदान के भुगतान और गौशालाओं के निरीक्षण का नियमित रिकॉर्ड रखा जाए। साथ ही, गोपालकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और पशु कल्याण के मानकों का पालन हो।

(पेज 1 का शेष)

विरोध के बाद कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई की स्थिति बनी। घटना कुशवाहा समाज के छात्रावास एवं सामुदायिक भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान हुई। इसी दौर में गुना से उनके तेवर वाले वीडियो सामने आते हैं, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक विरोध के आरोप लगते हैं और ग्वालियर में भाजपा के अंदर ही गुटिय खींचतान की चर्चा तेज होती है, तब सवाल बड़ा हो जाता है।

### गुना में 'नो रोड, नो वोट' ने बदल दिया संवाद का रंग

ग्वालियर की घटना के कुछ ही दिनों पहले गुना से एक और वीडियो चर्चा में आया। एक स्थानीय युवक ने सड़क की समस्या को लेकर सिंधिया से कहा कि सड़क नहीं बनी तो लोग वोट नहीं देंगे। जवाब में सिंधिया ने युवक से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करने को कहा। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजनीति में जनता और नेता के बीच संवाद का स्वर बहुत मायने रखता है। एक तरफ जनता अपने इलाके की सड़क, पानी, बिजली, रोजगार जैसी समस्याएं लेकर नेता के सामने आती है। दूसरी तरफ नेता के सामने सवाल होता है कि वह इन शिकायतों को किस तरह लेता है। गुना का यह वीडियो इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसमें जनता और नेता के बीच उस पुराने राजनीतिक संवाद की झलक दिखाई दी, जिसमें अब जनता सीधे सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ अधिकारियों को लेकर सख्त तेवर। इन घटनाओं ने सिंधिया की राजनीतिक शैली को फिर बहस के केंद्र में ला दिया है।

### ममता मीणा के आरोपों ने विवाद को और राजनीतिक बनाया

इसी बीच ममता मीणा ने सिंधिया पर राजनीतिक दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अपनी बात जनता तक ले जाने की

## 22 विधायकों के साथ कमलनाथ सरकार गिराई, सत्ता मिली लेकिन क्या सिंधिया ने खो दी अपनी पुरानी सियासी पकड़?



विजया ६

बात कही है। ये आरोप राजनीतिक विवाद के संदर्भ में लगाए गए हैं और इन्हें आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में आरोप भी तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब वे किसी ऐसे इलाके से आते हैं जहां पहले से ही राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा चल रही है। ग्वालियर-चंबल में भाजपा के भीतर कई स्थानीय चेहरे अपनी-अपनी

राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं।

### ग्वालियर की राजनीति में कौन किसके साथ है?

किस नेता का प्रभाव कितना है? किसकी बात संगठन में सुनी जा रही है? किस नेता के समर्थक खुद को राजनीतिक रूप से मजबूत मानते हैं? और

सबसे बड़ा सवाल- क्या सिंधिया की मौजूदगी अब भी ग्वालियर की पूरी राजनीति को अपने प्रभाव में समेट पाने की स्थिति में है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय की राजनीति में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिस ग्वालियर में 'महाराज' का प्रभाव था, वहीं अब टकराव क्यों?

### महाराज से 'भाई साहब' तक का सफर

'महाराज' की छवि उनके समर्थकों और ग्वालियर-चंबल की राजनीति में लंबे समय तक एक पहचान रही है। लेकिन भाजपा की संगठनात्मक राजनीति व्यक्तिगत राजघराने की छवि से अलग ढांचे पर चलती है। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। उनके साथ 22 विधायक भी भाजपा में आए और कमलनाथ सरकार गिर गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता का समीकरण बदल गया। आज कमलनाथ की सरकार होती तो प्रदेश में स्थिति अलग होती। यही वह जगह है जहां 'महाराज' और 'भाई साहब' की राजनीति का फर्क दिखाई देता है।

### 1857 से 2020 तक- सिंधिया नाम के साथ जुड़ी राजनीतिक बहस

सिंधिया परिवार का राजनीतिक इतिहास जितना लंबा है, उसके साथ जुड़ी राजनीतिक बहस भी उतनी ही पुरानी है। 1967 में विजयाराजे सिंधिया का कांग्रेस से अलग होकर जनसंघ की राजनीति से जुड़ना भी प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फिर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना और उनके समर्थक विधायकों का भाजपा में जाना। यानी सिंधिया परिवार की राजनीति में पाटी बदलने और सत्ता के समीकरण बदलने की चर्चा बार-बार लौटती रही है। 1857 की क्रांति में भी इस राजघराने ने देश के साथ गद्दारी की थी। आजादी का यह वह दौर था जब पूरा देश आजादी की लड़ाई में साथ खड़ा था लेकिन सिंधिया राजघराना अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया और रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा।

## लोहा चोर इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू अब सीबीआई के शिकंजे में

(पेज 1 का शेष)

और यदि निगरानी प्रणाली विफल रही है तो उस विफलता की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में सबसे बड़ी समस्या अपराध नहीं, बल्कि अपराध के बाद जिम्मेदारी से बचने की संस्कृति होती है।

### आर्थिक अपराध की उच्च श्रेणी में आता है लोहा चोरी का मामला

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से करोड़ों रुपये मूल्य के लोहे और स्क्रैप की कथित चोरी का मामला केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह देश के सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी खड़ा करता है। यदि इतने बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान से लंबे समय तक व्यवस्थित तरीके से लोहा और स्क्रैप बाहर जाता रहा, तो यह स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं निगरानी तंत्र में गंभीर खामियां मौजूद थीं। हाल के वर्षों में सामने आए इस प्रकार के मामलों ने यह आवश्यकता और भी बढ़ा दी है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच हो तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी बड़े औद्योगिक संयंत्र में स्क्रैप और उपयोगी धातु सामग्री का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया होती है। यदि चोरी का नेटवर्क लंबे समय तक सक्रिय रहा हो, तो यह केवल कुछ व्यक्तियों का मामला नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में अक्सर परिवहन, भंडारण, अभिलेख प्रबंधन तथा निगरानी व्यवस्था के विभिन्न स्तरों की जांच आवश्यक हो जाती है। यही कारण है कि जब किसी प्रकार में बड़े वित्तीय हित, अनेक पक्षों की संभावित संलिप्तता और व्यापक दस्तावेजी जांच की आवश्यकता होती है, तब स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की मांग उठती है।

### शिकंजे में होना चाहिए मगरमच्छ के साथ छोटी मछलियां

दावा किया जा रहा है कि पिछले करीब 40 वर्षों में संयंत्र से



विजया ६

लगभग 10 हजार करोड़ रुपये मूल्य का लोहा चोरी हो चुका है। इस दावे की वास्तविकता जांच का विषय है, लेकिन यदि इसमें तथ्य है तो यह अपने आप में अत्यंत गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई संगठित तंत्र सक्रिय रहा, तो उसकी पूरी श्रृंखला अब तक जांच के दायरे में क्यों नहीं आई? क्या पुलिस की जांच केवल चोरी के दौरान पकड़े गए छोटे आरोपियों और वाहनों तक सीमित रही या उन लोगों तक भी पहुंची, जिनके बारे में कथित तौर पर वर्षों से चर्चा होती रही है? सूत्रों का कहना है कि लोहा चोरी से प्राप्त रकम का 04 आईपीएस, 03 आईएएस और 12 राजनेताओं में बंटवारा होता है। गौरतलब है

कि इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू को भिलाई के प्रमुख ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में गिना जाता है। वे हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर हैं और कंपनी करीब 1,500 ट्रकों के संचालन से जुड़ी बताई जाती है।

### भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला

यह आपराधिक प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की कई अति गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से धारा 303(2), 317(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111, 112, 61(2)(क) तथा 3(5) शामिल हैं। इन सभी धाराओं में संगठित अपराध (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम), धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों का निर्माण और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोप संलिप्त हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आई सीबीआई की विशेषज्ञ टीम इस पूरे सिंडिकेट और नेटवर्क के अंतरंग पहलुओं की गहराई से जांच-पड़ताल करेगी।

### आशा है निष्कर्ष तक पहुंचेगी जांच

आवश्यक है कि जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न हो। दोषी चाहे किसी भी पद या स्तर का हो, उसके विरुद्ध समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, जांच के निष्कर्षों के आधार पर ऐसी व्यवस्थागत सुधारत्मक पहल भी की जानी चाहिए जिससे सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति सुरक्षित रह सके। बीएसपी से करोड़ों की लोहा चोरी का मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की परीक्षा भी है। देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि जांच एजेंसियां सत्य को सामने लाएं, दोषियों को कानून के दायरे में लाएं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जाएं। यही किसी भी लोकतांत्रिक और जवाबदेह व्यवस्था की मूल आवश्यकता है।

## सम्पादकीय

## मतदाता सूची पर उठे सवालों का जवाब पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही से ही संभव

लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया पर नागरिकों के भरोसे से तय होती है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है, क्योंकि करोड़ों मतदाताओं के मताधिकार की सुरक्षा इसी संस्था के कामकाज से जुड़ी है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों को महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही, आरोपों को बिना जांच के प्रमाणित तथ्य मान लेना भी उचित नहीं होगा। वर्तमान विवाद का प्रमुख केंद्र मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और निर्वाचन आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर सामने आई असहमतियाँ हैं। दो अन्य चुनाव आयुक्तों ने मतदाता पंजीकरण, सूची से नाम हटाने तथा डिजिटल प्रणालियों से जुड़े निर्णयों पर कई बार लिखित आपत्तियाँ दर्ज की थीं। विपक्षी दलों ने इन घटनाक्रमों को आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आधार बनाया है और मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर, ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को खारिज किया है और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्था में विचारों का मतभेद सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए पूरे प्रकरण का निष्पक्ष आकलन तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होना चाहिए। इस विवाद का सबसे गंभीर पहलू मतदाता सूची की विश्वसनीयता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना या संशोधित करना प्रशासनिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिक के संवैधानिक मताधिकार से है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट जाता है, तो वह चुनाव में भाग लेने के अवसर से वंचित हो सकता है। इसके विपरीत, अपात्र नामों को सूची में बने रहने देना भी चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता

है। इसलिए पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सटीकता के साथ मानवीय संवेदनशीलता, उचित सूचना और प्रभावी अपील व्यवस्था आवश्यक है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की संवैधानिक प्रकृति इस मामले को और महत्वपूर्ण बनाती है। निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग की स्वतंत्रता का उद्देश्य यही है कि चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर संचालित हो। आयोग के भीतर असहमति होना अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों पर मतभेद सामने आने के बाद उनकी प्रक्रिया और आधार स्पष्ट करना संस्थागत भरोसे के लिए जरूरी हो जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या किसी पदाधिकारी का इस्तीफा मांग लेना ही समाधान है? इस्तीफा राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न हो सकता है, लेकिन इससे मतदाता सूची संबंधी शिकायतों का स्वतः निवारण नहीं होगा। वास्तविक समाधान के लिए विवादित निर्णयों की समीक्षा, आवश्यक दस्तावेजों की जांच, प्रभावित मतदाताओं को सुनवाई का अवसर और त्रुटियों को सुधारने की समयबद्ध व्यवस्था जरूरी है। जहां कानून के उल्लंघन के प्रमाण मिलें, वहां निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, आरोपों की जांच में संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलना चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया भी संवैधानिक सुरक्षा से जुड़ी है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान निर्धारित प्रक्रिया और आधारों पर ही हटाया जा सकता है। यह व्यवस्था किसी पदाधिकारी को मनमानी की छूट देने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए बनाई गई है। इसलिए इस्तीफे की मांग और पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया के बीच अंतर समझना आवश्यक है।

## सियासी गहमागहमी

भाजपा में असंतोष के संकेत, सरकार-संगठन के तालमेल पर सवाल मध्यप्रदेश भाजपा में इन दिनों संगठन और सरकार के बीच समन्वय तथा नेताओं की नाराजगी का मुद्दा चर्चा में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी की बैठक में प्रशासनिक कार्यप्रणाली, अधिकारियों के रवैये और आपसी तालमेल से जुड़े मुद्दे उठाए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने सरकार के कामकाज को गति देने के साथ वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की चुनौती है। दूसरी ओर, संगठन की जिम्मेदारी भी यह सुनिश्चित करना है कि कार्यकर्ताओं की समस्याएं समय पर सुनी जाएं और असंतोष सार्वजनिक विवाद का रूप न ले। भाजपा के लिए वास्तविक चुनौती केवल असंतोष को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसके कारणों को समझकर समाधान करना है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा संगठनात्मक अनुशासन पर ध्यान देना जरूरी है। अंततः सरकार की कार्यक्षमता और जनता के प्रति जवाबदेही ही नेतृत्व की कसौटी होगी।

मप्र में राहुल गांधी के लगातार दौरें, संगठन को मजबूत करने की कवायद मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार दौरें प्रदेश की राजनीति में उनकी बढ़ती सक्रियता को रेखांकित करते हैं। भोपाल, पचमढ़ी और अब बालाघाट जैसे स्थानों पर उनकी उपस्थिति के अलग-अलग राजनीतिक और संगठनात्मक संदर्भ हैं। जून 2025 में उन्होंने भोपाल में संगठन सृजन अभियान से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया, जबकि नवंबर 2025 में पचमढ़ी में जिला अध्यक्षा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर जमीनी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। अक्टूबर 2026 में बालाघाट जिले के जगला गांव का दौरा कर उन्होंने आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी सुविधाओं से जुड़े सवाल उठाए। इन दौरों को केवल राजनीतिक उपस्थिति के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। कांग्रेस के सामने मध्यप्रदेश में संगठनात्मक मजबूती, स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता और जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने की चुनौती है। राहुल गांधी की यात्राएं इन मुद्दों को राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर महत्व देती हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि स्थानीय संगठन जनसमस्याओं को कितनी प्रभावी ढंग से उठाता है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता कितनी बढ़ती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़े नेताओं के दौरें तभी सार्थक होते हैं, जब उनके बाद जमीनी स्तर पर निरंतर काम दिखाई दे। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के लिए भी यही कसौटी महत्वपूर्ण रहेगी।

## हफ्ते का कार्टून



## ट्वीट-ट्वीट

देरावर में लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं - और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं।

Gen Z, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं - हर संघर्ष की आपनी कहानी है। पर जो आवाज अकेली उठती

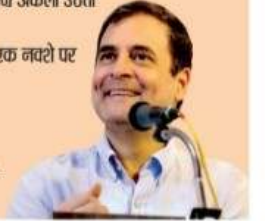
है, वो अक्सर दब जाती है।

'सत्याग्रह' इन्हीं आवाजों को एक नक्ते पर साथ लाने की पहल है।

बापू ने यही सिखाया था

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि निर्वाचन आयोग ने SIR के नाम पर देश को धोखा दिया है। SIR ने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटने का एक प्रमुख कारण 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग करना था।

-कमलनाथ

पूरा कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath



## राजवीरों की बात

छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर तय कर चुके हैं  
के.सी. वेणुगोपाल

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं, जिनकी पहचान चुनावी राजनीति के साथ-साथ संगठनात्मक कार्यों और पार्टी प्रबंधन से भी बनती है। के. सी. वेणुगोपाल कांग्रेस के ऐसे ही वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले वेणुगोपाल ने केरल की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी भूमिका का विस्तार किया है। विधायक, मंत्री, सांसद और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी के रूप में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। उनका जन्म 4 फरवरी 1963 को केरल के कन्नूर जिले के कंदोन्धर में हुआ। उन्होंने पय्यान्नूर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और कालीकट विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक तथा गणित में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। विद्यार्थी जीवन के दौरान ही उनकी रुचि सामाजिक गतिविधियों और राजनीति में विकसित हुई। वेणुगोपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र संगठन केरल स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) के माध्यम से राजनीति में कदम रखा। संगठन में उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्ष 1988 से केएसयू के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वर्ष 1993 से 2000 तक वे केरल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। छात्र और युवा संगठनों में काम करने के दौरान उन्हें कार्यकर्ताओं से संवाद, संगठन संचालन और राजनीतिक गतिविधियों का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे उनके राजनीतिक सफर का आधार बना। वेणुगोपाल ने वर्ष 1996 में केरल विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद 2001 और 2006 में भी वे विधानसभा पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने लगातार तीन कार्यकाल विधायक के रूप में बिताए। वर्ष 2004 में उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व वाली केरल सरकार में देवस्वम और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी मिली। इन विभागों के माध्यम से उन्हें राज्य के प्रशासन, धार्मिक संस्थानों और पर्यटन से जुड़े विषयों पर काम करने का अवसर मिला। वर्ष 2009 में वेणुगोपाल अलपुझा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। वर्ष 2011 में उन्हें केंद्र की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में विद्युत राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में उन्होंने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। वर्ष 2014 में वे दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न समितियों में भी काम किया। वर्ष 2020 में वे राज्यसभा से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2024 में राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और अलपुझा से फिर निर्वाचित हुए। वेणुगोपाल को 29 अप्रैल 2017 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक और चुनाव संबंधी दायित्व निभाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में उनकी भूमिका संगठन के कामकाज, राज्यों में पार्टी की गतिविधियों और चुनावी तैयारियों से जुड़ी रही है। संसद में भी उनकी सक्रियता जारी रही। अगस्त 2024 में वे लोकसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। यह समिति सरकारी व्यय और विनियोग से संबंधित विषयों की संसदीय जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

## मुख्यमंत्री धामी ने गांधी एवं शास्त्री के चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किये

-प्रमोद कुमार

**जगत प्रवाह.** देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और मानवता के सिद्धांत सदैव समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता के लिए प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

## सत्य, अहिंसा और सादगी के आदर्श हमें राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देते रहेंगे: मुख्यमंत्री साय

-शशि पांडे

**जगत प्रवाह.** रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और मानवता के मार्ग पर चलते हुए पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया। उनके विचारों में समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण और आत्मनिर्भर भारत की भावना निहित थी। उनका जीवन हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है।

## बाल कैंसर सर्वाइवर्स की स्वास्थ्य जांच, फन फेयर में झलका उत्साह



-संतोष सिंह कुशवाह

**जगत प्रवाह.** ग्वालियर। बाल कैंसर जागरूकता माह के तहत कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 29 एवं 30 सितंबर को बाल कैंसर सर्वाइवर्स के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर एवं फन फेयर आयोजित किया गया। शिविर में 70 बाल कैंसर सर्वाइवर्स ने अपने माता-पिता के साथ सहभागिता की। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक परीक्षण किए, वहीं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी की डॉ. संध्या गर्ग ने विशेष सत्र लिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित फन फेयर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वर्गीय राजीव सहाय, श्रीमती सहाय तथा शीतला सहाय को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस दौरान CHRI निदेशक डॉ. बी.आर. श्रीवास्तव, डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, डॉ. गुंजन श्रीवास्तव, डॉ. जी.एस. राजपूत सहित रोटर एवं रोटेक्ट क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। एएमआई शिशु मंदिर के विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। बच्चों को कप, केक, बैग, रिस्टबैंड, क्राउन एवं विशेष किट वितरित की गई। रोटरियन सुचेता बोस लाहा एवं रैना बनर्जी ने कहानी वाचन किया, जबकि बाल कैंसर सर्वाइवर्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर माहौल में उमंग भर दी। CHRI निदेशक डॉ. बी.आर. श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के मनोरंजन के साथ उनके आत्मविश्वास और मानसिक-भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहुल गांधी कल मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के दौरे पर थे, आदिवासी बच्चों की गीत से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी।

## गांधी जयंती पर झुनकु नदी में चला वृहद स्वच्छता अभियान

-अमित राजपूत

**जगत प्रवाह.** देहरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती एवं 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत झुनकु नदी में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के नेतृत्व में आयोजित अभियान में नगर पालिका अधिकारी-कर्मचारियों एवं सफाई मित्रों ने सहभागिता करते हुए नदी में सफाई कार्य किया। इस अवसर पर स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी और जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि "स्वच्छ देवरी, स्वस्थ देवरी- यही हमारा संकल्प है।" उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही स्वच्छ एवं सुंदर देवरी की पहचान कायम की जा सकती है। अभियान के दौरान झुनकु नदी क्षेत्र में सफाई कर नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उपयंत्री अजीत सिंह भुवें, कृष्ण पांडे, मनु जारोलिया, शंभू वात्सवीक, नरेंद्र दीक्षित, मुकेश नामदेव, बबलू प्रजापति सहित नगर पालिका अधिकारी और सफाई मित्र उपस्थित रहे।



## माधवराव सिंधिया स्मृति हिंदी वाद-विवाद में सिंधिया स्कूल प्रथम

-संतोष सिंह कुशवाह

**जगत प्रवाह.** ग्वालियर। महाराजा माधवराव सिंधिया की स्मृति में सिंधिया स्कूल, दुर्ग ग्वालियर में 25वीं महाराजा माधवराव सिंधिया स्मृति अंतरविद्यालयीय हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में देश के 10 प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न चरणों के बाद सिंधिया स्कूल ग्वालियर ने प्रथम तथा संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सिंधिया स्कूल के खूश टोडी को सर्वश्रेष्ठ वक्ता और संत अतुलानंद स्कूल के सनत सिंह को सर्वश्रेष्ठ प्रश्नकर्ता चुना गया। इसी अवसर पर बुनो कहानी, कहो जुबानी प्रतियोगिता में सिंधिया कन्या विद्यालय की छात्रा श्रुति सिंघेल प्रथम रही। निर्णायकों ने विद्यार्थियों को वाद-विवाद एवं कहानी कला की बारीकियों से परिचित कराया। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और विद्यार्थियों से महाराजा माधवराव सिंधिया के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय सिंह, मनोज मिश्रा, हिंदी विभागाध्यक्ष रक्षा सीरिया सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।



## 'दिशा 2026' का आगाज, विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

-संतोष सिंह कुशवाह

**जगत प्रवाह.** ग्वालियर। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (IITM) ग्वालियर में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'दिशा 2026' का उत्साहपूर्ण आगाज हुआ। आयोजन के प्रथम चरण में ब्रेनस्टॉर्मिंग, पॉट पेंटिंग एवं इटिनेररी प्रिपरेशन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने त्वरित सोच, तार्किक क्षमता और नवीन विचारों का परिचय दिया। वहीं पॉट पेंटिंग में साधारण मटकों को आकर्षक रंगों और डिजाइनों से सजाकर विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा के साथ भारतीय लोक कला के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित की। इटिनेररी प्रिपरेशन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पर्यटन स्थलों, यात्रा मार्ग, समय-प्रबंधन, प्रमुख आकर्षणों और पर्यटक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित यात्रा कार्यक्रम तैयार किए। निदेशक डॉ. प्रशांत के. गौतम ने कहा कि 'दिशा 2026' जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों की रचनात्मकता, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और टीमवर्क को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नोडल अधिकारी डॉ. सौरभ दीक्षित ने कहा कि प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करती हैं। इस अवसर पर डॉ. चंद्र शेखर बरआ, एवं सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. कमाशी मोहेश्वरी ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।



# ब्रिक्स सम्मेलन एक लेखा-जोखा



**रघु ठाकुर**  
सामाजिक कार्यकर्ता,  
विचारक और  
समाजवादी नेता

12 देशों के संगठन बिस्व का त्रि-दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर को समाप्त हो गया है, इस सम्मेलन से भारत सरकार के मुखिया और उनकी पार्टी के लोगों को कुछ राहत मिली होगी कि प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी के वैश्विक नेता होने की एक छद्म प्रतिमा तीन दिनों तक लगातार अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर रही और चर्चा में रही तथा पिछले दिनों जो घटनायें देश में हुई थीं जिनको लेकर लगातार प्रतिपक्ष की ओर से आरोपों की बौछार तथा जनचर्चा थी उस पर भी कुछ विराम लगा। हालांकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर और वैचारिक तौर पर इस बिस्व सम्मेलन से कोई आशा तो छोड़िये बल्कि निराशा ही हुई है। एक तो इसलिये कि यह देश में वैश्विक स्तर की होने वाली घटना थी जिसमें बिस्व के सदस्य और अन्य आमंत्रित लगभग 28 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे थे, परंतु 1948 से भारत सरकार ने जो एक राष्ट्रीय शिष्टाचार की परंपरा रही है उसका भी पालन नहीं किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर विदेशी मेहमानों को नहीं ले जाया गया। इसके पहले जब जी-20 देशों के समूह का आयोजन देश में हुआ था, (वर्ष 2024) में कम से कम तब सरकार ने यह शिष्टाचार निभाया था कि जी-20 के मेहमानों को राष्ट्रपति की समाधि पर ले गये थे। महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर सम्मान प्रकट करने से गांधी के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु देश का सम्मान बढ़ता है। यह सरकार की स्वीच्छक भूल है या असावधानी पर जो भी घटित हुआ, इस घटना ने देश के एक बड़े हिस्से के मन में चोट पहुंचाई है। मेरी दूसरी निराशा बिस्व के उस सामूहिक वक्तव्य को लेकर भी है जो 45 पेज के 140 विंदुओं में है, पर जिसमें चीन के साथ बातचीत बातचीत में प्रधानमंत्री ने चीन के द्वारा भारतीय सीमाओं पर कब्जे के प्रश्न को लगभग चुप रहकर दृष्टि ओझल किया है। श्री मोदी ने सम्मेलन से इतर श्री जिनिफ्रि से निजी बातचीत में कहा कि शसीमा से जुड़े समझौतों और सहमतियों का पालन हो। दोनों ने सीमा विवाद का निष्पक्ष और स्वीकार्य हल निकालने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बातचीत

निर्णय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के उन नक्शों की बात नहीं उठाई जिसमें चीन अण्णाचल व लद्दाख से सटे इलाके को अपना बताता है। जो पुरानी भारतीय भूमि 1962 में चीन के हमले द्वारा कब्जाई गई थी, गलवान घाटी और डोकलाम में जो भारतीय भूमि में चीन ने कब्जा जमाया है उसको कोई चर्चा नहीं की। बस केवल व्यापार की चर्चा हुई और इस चर्चा में भी भारत सरकार अपने पुराने निर्णयों से पलट गई। अभी मुश्किल से एक डेढ़ वर्ष पूर्व हमारी बहादुर भारत सरकार राष्ट्रबंद, स्वदेशी और भारतीय सीमाओं के नाम पर चीन के 28 ऐस्पे बंद किये थे और अब न केवल वे 28 ऐस्पे बल्कि अन्य बहुत सारे ऐस्पे सक्रिय रहेंगे। याने इस ब्रिक्स सम्मेलन में भारत सरकार ने राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय सीमा, और राष्ट्रीय विचारस्य तीनों को ठेस पहुंचाई। ब्रिक्स सम्मेलन महज तीन साल में होने वाले कार्यक्रम के रूप में एक औपचारिकता सिद्ध हुआ है। यह आश्चर्यजनक है कि श्री विदर्भम व अन्य कांग्रेसी सांसदों ने इस घोषणा पत्र की सराहना की है, क्योंकि राष्ट्रीय सीमा पर चीनी कब्जे की अपराधी उनकी सरकार भी रही है। जो लोग इस भ्रम में हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन से अमेरिका के खिलाफ या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोई गोलबंदी होगी तो वे भी भ्रम में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पीवी नरसिंह राव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद और देश की राजनैतिक जरूरत को समझकर भारत की विदेश नीति को बदला था और लुक द ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी। ब्रिक्स भी एक अर्थ में इसी विचार का विस्तार है। वैसे तो 1962 में भारत पर चीनी हमले के लगभग 23 वर्ष के बाद पहली बार स्वर्ण राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर और 1978 में 48 वर्ष पूर्व स्वर्ण अटलबिजारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में चीन की पहली यात्रा की थी।

पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि ब्रिक्स की नई मुद्रा होनी चाहिए परंतु यह आसान निर्णय नहीं था और इसलिये अंत में इतना ही कहा गया कि ब्रिक्स के देश अपनी मुद्रा में आपस में विनमय कर सकते हैं। ब्रिक्स की कोई अलग से मुद्रा नहीं बनेगी, इसलिये डालर को कोई हूट पट चुनीती भले मिले परंतु उस को कोई विशेष चुनीती नहीं है। जहां तक यह कहना कि नाटो देशों का व्यापार दुनिया के व्यापार का 29 प्रतिशत है और ब्रिक्स देशों का व्यापार 40 प्रतिशत है। यह भी एक प्रचारामय आंकड़ा है। भारत सरकार के ट्रंप को घेरने का सपना भी अभूरा ही रहा है, क्योंकि अगले कुछ माह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। पुतिन और ट्रंप की दोस्ती तो जग जाहिर है। जहां तक व्यापार का प्रश्न है तो जो आपसी समझौते हुए हैं, उन्हें बाहरी को से देखने पर लगता है कि इसका बड़ा लाभार्थी चीन और रूस है। विश्व शांति के सवाल पर भी कोई भूमिका ब्रिक्स अदा नहीं कर सका। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही ब्रिक्स के हिस्से हैं तथा ईरान समर्थित हथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के



तेल के ठिकानों पर ईरान की शह पर हमला किया है। जिसकी आवां मक्का तक पहुंची है। ईरान के राष्ट्रपति पोजेस्कियान आये थे परंतु यह सुविदित तथ्य है कि ईरान की वास्तविक सत्ता भूमि गुरु खामनेई के हाथ में है। पोजेस्कियान की स्थिति लगभग याकृत के राष्ट्रपति जैसी है। रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रोकने के लिये कोई टोस चर्चा नहीं हो सकी।

यहां तक चीन से रेयर मिनिरलस को आयात करने का सवाल है तो उस पर चीनी मुखिया श्री जिनिंग ने अपने भाषण में श्री नरेन्द्र मोदी की अपील का कोई उल्लेख नहीं किया। जबकि रेयर मिनिरलस और विशेषतरू परमाणु ऊर्जा और शक्ति के लिये मिनिरलस का चीन के पास भण्डार है।

यह कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत का बिस्व देशों को नियात दुगुना हो जायेगा। पर यह नहीं बताया जा रहा है कि बिस्व देशों से विशेषतरु चीन-रूस-ईरान से, भारत का आयात कितने गुना बढ़ जायेगा। 2025 तक चीन से आयात 132 अरब डालर था, तथा व्यापार घाटा (अधिक आयात) 112 अरब डालर का है और अब, यह व्यापार घाटा याने आयात कई गुना बढ़ेगा। फिर भी, मीडिया का बड़ा हिस्सा, इसे मोदी की सफलता बता रहा है। ऐसे लगता है कि बिस्व सम्मेलन महज एक और्च्चारिक सम्मेलन बनकर रह गया। इसके नियमानुसार 3 वर्ष में यह एक बार किसी सदस्य देश में होता है। अगले 3 वर्ष बिस्व यह चीन में आयोजित होगा। इसकी उपलब्धि इतनी ही कही जा सकती है कि इसमें शामिल होने वाले देशों ने अपनी अपनी जरूरतों के व्यापार की संभावनायें तलाशी हैं। उन्हें आपस में समझा है और अब अपने अपने लाभ और जरूरत के हिसाब से यह देश फैसला करेंगे। यह बैठकों में, सम्मेलनों में भी और उसके बगैर आपसी चर्चा व आदान प्रदान से भी होता है।

यूरोप के जो देश नाटो के सदस्य हैं, उनके व अमेरिका के बीच मतभेद का यही मुख्य कारण है कि अमेरिका रूस के खिलाफ टैरिफ लगाकर रूस की शक्ति व आक्रामकता को रोकना चाहता है। लगभग 30 हजार किस्म के प्रतिबंध रूस के खिलाफ दुनिया के देशों ने लगाए हैं, ऐसा पतिन ने अपने भाषण में दिल्ली में कहा।

है। अमेरिका चाहता है कि नाटो के देश और भारत रूस के तेल व्यापार को कमजोर करने के सहयोगी बनें ताकि रूस के आर्थिक साधन कमजोर हों और रूस के द्वारा यूक्रेन पर थोपा युद्ध रोकता जा सके और पुतिन भी यूक्रेन को अमेरिका के समर्थकों से वंचित कर अपनी यूक्रेन पर जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों के इन तीन बड़े देशों के अपने अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण हैं, जिनका चातुर्य व ढके शब्दों में पुनरुक्त उन्होंने भारत की राजधानी में खुलासा कर दिया। इतना ही इस सम्मेलन से हासिल हो सका है। दुनिया एक नये विश्व युद्ध की ओर जा रही है, जिसकी गंभीरता पर कोई चर्चा ब्रिक्स में नहीं हुई। ईरान का समर्थन प्राप्त हवी विद्रोही अब अरब देशों पर और

विशेषतः सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, जो लगातार जारी है। वैसे तो यह हमले अरब देशों के अमेरिकी कारखानों व सामरिक ठिकानों पर करने के उद्देश्य से बताये जा रहे हैं परंतु उससे दुनिया पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वे भविष्य में एक नये युद्ध की संभावना की ओर जा रहे हैं। एक तो सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हूती हमलावरों पर सऊदी अरब ने लाचार होकर तेल निर्यात को सीमित किया है। इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ेगा साथ ही यूरोप के देशों पर विशेषतौर पर पड़ेगा। क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में समर्थन के कारण उन्होंने रूस से तेल लेना बंद किया है और उनकी तेल आपूर्ति का बड़ा माध्यम खाड़ी देश ही हैं। वैश्विक स्तर पर इस हमले के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़कर 104 डालर प्रति बैरल के आसपास पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब और खाड़ी देश इस्लाम के सूनी समुदाय के देश हैं। ईरान तथा हूती विद्रोही शिया मुस्लिमों के देश हैं। यह विवाद भीतर-भीतर दुनिया के इस्लामिक मंच पर शिया और सूनी के प्रभाव व कब्जे के प्रयास में भी बदल रहा है और इसके परिणाम स्वरूप यह छद्म धर्मयुद्ध और परमाणु युद्ध की शकल भी ले सकता है। याने एक नये विश्व युद्ध का केंद्र बन रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन में इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। विश्व के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं होना भी असफलता ही मानी जानी चाहिए।

## छात्रों के साथ मिड-डे मील में शामिल हुए मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी

-अमित राय

**उगत प्रवाह.** हावड़ा बेंटरा थाना अंतर्गत मधुसूदन पॉल चौधरी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुवेन्दु अभिकारी ने राज्य के कई विद्यालयों के लिए "सारीथी योजना" का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय की शैक्षणिक एवं आभारभूत व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मिड-डे मील की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और बच्चों के साथ बैठकर मिड-डे मील का आनन्द लिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मोबाइल फोन से दूर रहना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की ओर से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मोबाइल खरीदने के लिए दी जाने वाली 11 हजार रुपये की राशि की व्यवस्था को बंद कर अब एजुकेशनल टैब देने की योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि भले ही इस व्यवस्था में 10 हजार रुपये अधिक खर्च हों, लेकिन बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हुए शिक्षा के लिए टैब उपलब्ध कराने की व्यवस्था



की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साइकिल वितरण योजना को लेकर भी पिछली व्यवस्था कि पहले विद्यार्थियों को ही जाने वाली साइकिलें लुधियाना से आती थीं और यहाँ लाकर उन्हें असेंबल किया जाता था। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस काम से जुड़ी पिछली व्यवस्था को बंद कर दिया गया है और सरकारी धन की बर्बादी रोकने पर जोर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि मिड-डे मील के रोजाना निर्धारित मेनू के अनुसार ही भोजन तैयार किया गया था। मेनू में भात, दाल, आलू-सोयाबीन की सब्जी और चटनी शामिल थी। हालाँकि, रोज की तुलना में भोजन कुछ अधिक मात्रा में तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री सहित सभी ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन का आनंद लिया।

श्राद्ध: स्मृतियों से आगे, विरासत तक

# क्या हमने अपने पूर्वजों के आदर्शों को अपनाया है

आज की बात



प्रवीण कुलकर्णी  
स्वतंत्र लेखक

श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। सभी घरों में पूर्वजों को याद किया जा रहा है और उनकी स्मृति में दान-धर्म तथा भोजन के आयोजन हो रहे हैं लेकिन इन सबके बीच मेरे मन में एक सवाल भी है- क्या हम अपने पूर्वजों के आदर्शों और उनकी अच्छी बातों को सचमुच अपना पाए हैं? क्या उनकी स्मृति में भोजन कराने और दान देने के साथ-साथ हमने उनके जीवन-मूल्यों को अपने व्यवहार में जगह दी है? श्राद्ध पक्ष में ये सवाल केवल परंपरा निभाने के नहीं, अपने भीतर झाँकने के भी हैं। श्राद्ध हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता

व्यक्त करने का अवसर है। यह उन लोगों को याद करने का समय है, जिनके श्रम, संस्कार और फैसलों ने हमारे लिए जीवन की राह बनाई। लेकिन स्मृति तभी सार्थक होती है, जब वह हमारे वर्तमान को दिशा दे। तर्पण में अर्पित जल की तरह उनके अच्छे विचार भी हमारे आचरण में उतरें, तभी यह जुड़ाव अगली पीढ़ी तक पहुँचेगा।

## कृतज्ञता का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं

श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध से किया गया भोजन, दान और तर्पण हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका अपना आध्यात्मिक और भावनात्मक अर्थ है। पर क्या हमारी जिम्मेदारी यहीं पूरी हो जाती है? जिस बुजुर्ग ने ईमानदारी से जीवन बिताया, क्या उनकी स्मृति में हम अपने काम में ईमानदारी रख पाते हैं? जिसने परिवार को जोड़कर रखा, क्या हम अपने रिश्तों को समय और सम्मान देते हैं? जिसने कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा, क्या हम पहली परेशानी में हार मानने से बचते हैं? पूर्वजों का असली तर्पण शायद यही है कि उनके जीवन से मिली सीख हमारे निर्णयों में दिखाई दे। उनके नाम पर अर्पित भोजन और दान के साथ, उनके संस्कार भी हमारे स्वभाव का हिस्सा बनें।



## छोटी यादों में बड़े संस्कार

हममें से अधिकतर लोगों के पास अपने बुजुर्गों की कुछ ऐसी यादें हैं, जो किसी किताब में दर्ज नहीं, किसी का बिना शिकायत काम करते रहना, किसी का मेहमान को खाली हाथ न लौटाना, किसी का कठिनाई में पड़ोसी के साथ खड़ा होना, या किसी का बच्चों को कहानी सुनाते हुए जीवन की बड़ी सीख दे जाना। ये छोटी बातें थीं, पर इन्हीं से घर और समाज का चरित्र बनता था।

## समय बदले, मूल्य नहीं

समय बदलता है, जीवन की सुविधाएँ और चुनौतियाँ भी। हर पुरानी बात को ज्यों का त्यों अपनाना संभव या जरूरी नहीं लेकिन विवेक, करुणा, श्रम, सादगी, सत्यनिष्ठा और सामूहिकता जैसे मूल्य किसी एक समय के मोहताज नहीं होते। सवाल यह है कि नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए हमने इन मूल्यों को अपने जीवन में कितना बचाकर रखा है।

## परिवार से देश तक

यही प्रश्न परिवार से आगे बढ़कर देश तक जाता है। भारत की

साझी विरासत किसी एक इमारत, पुस्तक या उत्सव का नाम नहीं है। यह अनेक समुदायों, भाषाओं, परंपराओं और पीढ़ियों के योगदान से बनी जीवन-दृष्टि है - विविधता के बीच साथ रहना, संवाद करना, ज्ञान का सम्मान करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना और जरूरत के समय एक-दूसरे के काम आना।

## अगली पीढ़ी के नाम क्या छोड़ेंगे?

हमारे पूर्वजों ने इस विरासत को अपने ढंग से गढ़ा और सँभाला। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे केवल गौरव के शब्दों में न दोहराएँ, बल्कि अपने व्यवहार में भी जगह दें। क्या हम इसे सहेज पा रहे हैं? क्या हम अगली पीढ़ी को यह विरासत केवल किस्सों में सौंपेंगे, या ऐसा समाज भी देंगे जहाँ इसके मूल्य अनुभव किए जा सकें?

## बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं

विरासत अगली पीढ़ी तक केवल भाषणों से नहीं पहुँचती। बच्चे यह देखते हैं कि हम बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करते हैं, मतभेद के समय कितने संयमित रहते हैं और अपने से अलग विचार रखने वालों के प्रति कितना सम्मान दिखाते हैं। हम उन्हें जो कहते हैं, उससे अधिक वे हमारे रोजमर्रा के आचरण से सीखते हैं। श्राद्ध पक्ष हमें पीछे मुड़कर देखने का अवसर देता है लेकिन उसका उद्देश्य वहीं ठहर जाना नहीं, आगे की जिम्मेदारी पहचानना है। हम अपने पूर्वजों को याद करें, पर साथ ही यह भी पूछें कि उनकी कौन-सी अच्छी बात आज हमारे जीवन में जीवित है। उनके प्रति श्रद्धा तभी पूर्ण होगी, जब उनकी सीख हमारी अगली पीढ़ी तक पहुँचे।

## पीढ़ियों तक चलने वाली श्रद्धांजलि

इस श्राद्ध पक्ष में भोजन और दान के साथ एक संकल्प भी लें - परिवार और समाज को जोड़ने वाले गुणों को अपने जीवन में उतारने का, और अपनी साझी विरासत को समझकर सहेजने का। क्योंकि पूर्वजों की स्मृति में किया गया तर्पण एक दिन का कर्म हो सकता है, पर उनके आदर्शों को अपनाना पीढ़ियों तक चलने वाली श्रद्धांजलि है।

# देवतात्मा हिमालय पर प्रदूषण का आक्रमण

पर्यावरण की फिक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा  
पर्यावरणविद

हिमालय को दुनिया की सबसे स्वच्छ और प्राकृतिक अखंड श्रृंखलाओं में गिना जाता रहा है। हिमालय, जो कभी धरती का सबसे पवित्र और निर्मल प्राकृतिक किला माना जाता था, आज प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। हिमालय अब केवल जलवायु परिवर्तन की मार नहीं झेल रहा है बल्कि मैदानों से पहुँच रहे प्रदूषण और पहाड़ों के भीतर तेजी से बढ़ते वाहनों, पर्यटन, तीर्थयात्रा, निर्माण और जंगलों में आग और पेड़ों की कटाई भी उसकी हवा में प्रभावित कर रहा है। भारतीय सभ्यता के लिए हिमालय केवल पत्थर बर्फ

और ऊँचाई का नाम नहीं रहा। कालिदास ने कुमार संभव में लिखा: अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः। "देवतात्मा" शब्द को समझने की आवश्यकता है। विज्ञान हिमालय को भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वततंत्र, जलवायु नियंत्रक क्षेत्र और जैव विविधता के लिए जरूरी मानता है। भारतीय परंपरा इसे पवित्र सत्ता और जीवन के रूप में समझा। विज्ञान हमें बताता है कि हिमालय कैसे काम करता है, परंपरा यह सवाल उठाती है कि इसके साथ हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययनों से पुष्ट हो रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक, काला कार्बन और ओजोन जैसे विषाणु कण अब केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हिमालय की ऊँचाइयों यहाँ तक कि एवरेस्ट क्षेत्र की 5,000 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक पहुँच चुके हैं। माइक्रोप्लास्टिक



प्लास्टिक के पाँच मिलीमीटर से छोटे कण होते हैं।

## हालिया शोधों में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:

नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में 2,860 से 5,364 मीटर की ऊँचाई तक ओजोन की सांद्रता 100 पीपीबी से अधिक पाई गई है। एक अनुसंधान गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। अध्ययन में 19 दिसंबर 2025 को जमीन के निकट ओजोन की आठ घंटे की औसत सांद्रता 634.13 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज हुई, जबकि एक घंटे का स्तर 880 माइक्रोग्राम से ऊपर चला गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी ओजोन के लिए आठ घंटे का मानक 100 और एक घंटे

का 180 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर निर्धारित किया है। एवरेस्ट के निकट 5,079 मीटर ऊँचाई पर स्थित नेपाल क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी में मानसून-पूर्व अवधि में ओजोन का औसत 60.9 पीपीबी दर्ज किया गया। तिलिचो झील (4,917 मीटर) जैसे ऊँचे हिमालयी जलाशयों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पुष्ट हुई है, जहाँ पर्यटन और प्लास्टिक कचरा प्रमुख स्रोत हैं।

गंगा और यमुना की हिमालयी सहायक नदियाँ जैसे रिसपाणा, बिंदाल और टॉस में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 0.1 से 10.95 कण प्रति लीटर पाई गई। धौलाधार श्रृंखला से निकलने वाली नदी उहल के जल और तलछट में भी माइक्रो प्लास्टिक के कण व्यापक रूप से मिले हैं।

इस प्रदूषण के पीछे मुख्य कारणों में दक्षिण एशिया से उठने वाला वायु प्रदूषण, बेरोकटोक पर्यटन, प्लास्टिक कचरे का अनुचित निस्तारण और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना शामिल है। प्रदूषण के ये कण न केवल हिमालय की बर्फ को काला कर रहे हैं, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बल्कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे महाद्वीपीय नदी तंत्रों के माध्यम से लगभग दो अरब लोगों की जल सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं।

इसके अलावा भी कई कारण हैं जिससे भारतीय हिमालय क्षेत्र, जिसे "दक्षिण एशिया का जलस्तंभ" कहा जाता है, एक गहराते पारिस्थितिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हिमालय भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियों का श्रोत है जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु शामिल हैं। हिमालय का प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व का संकट बन चुका है। यदि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप, सतत पर्यटन प्रबंधन और जन-जागरूकता के माध्यम से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो "देवतात्मा" कहलाने वाला यह पर्वत श्रृंखला भविष्य में मानवजनित प्रदूषण का सबसे ऊँचा प्रतीक बनकर रह जाएगा।



**Chhattisgarh**  
Business Made  
Easy



श्री विष्णु देव साय  
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री

# छत्तीसगढ़: उद्योगों से भविष्य का निर्माण

नए क्षेत्रों में तेज़ विस्तार | निवेश धरातल पर | युवाओं के लिए रोजगार

**₹ 8.23 लाख करोड़**

अब तक की निवेश प्रतिबद्धताएँ

**1.5 लाख+**

अपेक्षित रोजगार

**50% श्रष्ट**

सेक्टर परियोजनाएँ

## नए क्षेत्रों में प्रगति

- नवा रायपुर में भारत का पहला **एआई डेटा सेंटर**
- मध्य भारत का सबसे बड़ा **फार्मा पार्क**
- नवा रायपुर में राज्य का पहला **सेमीकंडक्टर प्लांट**
- भारत के सबसे बड़े **पेट फूड** ब्रांड का विनिर्माण केंद्र
- नवा रायपुर में **गारमेंट पार्क**, वस्त्र उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन



हमसे जुड़ने के लिए  
QR स्कैन करें

[/ChhattisgarhCMO](#)  
[/DPRChhattisgarh](#)  
[www.dprcg.gov.in](http://www.dprcg.gov.in)



छत्तीसगढ़ की पहचान अब केवल उसकी खनिज संपदा से नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण, वास्तविक परियोजनाओं, नए रोजगार और विविध आधुनिक अर्थव्यवस्था से भी है।

- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़